


17/8
11/8/2006

1-5-2006
CSR-03

1/20

Registration Copy

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  सत्यमेव जयते | राजस्थान राज-पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 20, सोमवार, शाके 1928-अप्रैल 10, 2006 Chaitra 20, Monday, Saka 1928-April 10, 2006 | |

भाग 4 (क)

BX-3145

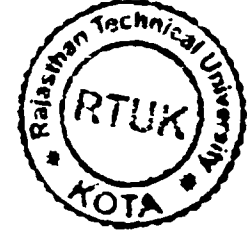
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 9, 2006



संख्या प. 2 (9) विधि/2/2006.-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम सं. 8)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 है।

राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह 31 दिसम्बर, 2005 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (i) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की धारा 24 के अधीन यथागटित विद्या परिषद् अभिप्रेत है ;
- (ii) "सम्बद्ध महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है;
- (iii) "अ. भा. त. शि. प." से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
- (iv) "प्राधिकारी" से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत हैं ;
- (v) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का धारा 22 के अधीन यथागटित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (vi) "निकाय" से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये विश्वविद्यालय के निकाय अभिप्रेत हैं ;
- (vii) "सहयोग" से विश्वविद्यालय की अन्य विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय), अनुसंधान संस्थाओं और संगठनों (अनुसंधान, कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य) के साथ सहयोगी शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं ;

- (viii) "घटक महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो तकनीकी शिक्षा देती है और विश्वविद्यालय द्वारा चलायी और संधारित की जाती है और इसमें विश्वविद्यालय का कोई संकाय सम्मिलित है ;
- (ix) "संकायाध्यक्ष" से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (x) "विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित और प्रबन्धित कोई विभाग अभिप्रेत है;
- (xi) "निदेशक" से किसी केन्द्र को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की किसी संस्था या विद्यापीठ का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथापदाभिहित प्रधान अभिप्रेत है;
- (xii) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;
- (xiii) "सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था" से राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कोई तकनीकी संस्था अभिप्रेत है;
- (xiv) "संस्था" से सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाएं और प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाएं अभिप्रेत हैं;
- (xv) "प्रबन्ध" से राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का न्यासी या प्रबन्ध या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है जिसके प्रबन्ध के अधीन एक या अधिक महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाएं या अन्य

संस्थाएं संचालित की जाती हैं और जिन्हें विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाते हैं;

- (xvi) "आर्डिनेन्स" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स अभिप्रेत हैं;
- (xvii) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय, सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;
- (xviii) "गैर-सहायताप्राप्त प्राइवेट तकनीकी संस्था" से तकनीकी शिक्षा का उपाधि या डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अ.भा.त.शि.प. के पूर्व अनुमोदन से किसी प्राइवेट प्रबन्ध द्वारा स्थापित कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत हैं जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही है;
- (xix) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;
- (xx) "परिनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;
- (xxi) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसन्धान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (xxii) "तकनीकी शिक्षा" से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंध, नगर योजना, फार्मसी, कम्प्यूटर उपयोजन और अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्प और ऐसे अन्य कार्यक्रमों, जो अ.भा.त.शि.प. द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किये

जायें, - में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत हैं;

- (xxiii) "तकनीकी संस्था" से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं अभिप्रेत हैं;
- (xxiv) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत हैं;
- (xxv) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और संधारित कोई विभाग अभिप्रेत है;
- (xxvi) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई अध्यापक अभिप्रेत है।

अध्याय 2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन.—(1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अन्तरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

7(6) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:—

(i) सामान्यतया अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान के द्वारा मानवता और समझदारी की अभिवृद्धि के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार, सृजन और अनुसंधान करना और विशिष्टतया :—

(क) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध और अन्य तकनीकी संस्थाओं के समग्र गुणवत्ता और लागत प्रभावी प्रबन्ध को प्रोन्नत करना;

(ख) उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में तकनीकी शिक्षा का तंत्र उपलब्ध कराना;

(ग) तकनीकी शिक्षा के लिए निर्णय करने और सूचना प्रणालियों के वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित प्रबन्ध की प्रणाली सृजित करना;

(ii) पाठ्यक्रम में अनुप्रयुक्त संघटकों के माध्यम से कार्य संस्कृति का विकास और श्रम की गरिमा को प्रोन्नत करना और छात्रों में उद्यमशीलता को प्रोन्नत करना जिससे तकनीकी शिक्षा को रोजगार चाहने वालों का सृजन करने के बजाय रोजगार सृजन का सबल साधन बनाया जा सके;

(iii) विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बीच सभी साधनों द्वारा बेहतर परस्पर क्रिया और समन्वय को प्रोन्नत करना, सामान्यतया विश्वविद्यालय के शासन और तकनीकी शिक्षा में

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(7)
उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं में सुधार करना;

- (iv) समाज के कमजोर वर्गों के बीच आत्मसम्मान और गरिमा की भावना जाग्रत और प्रोन्नत करना;
- (v) छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षणिक और अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक मानदण्ड के रूप में प्रतियोगी गुणागुण और उत्कर्ष के प्रोन्नयन का प्रयास करना;
- (vi) अपने शैक्षणिक उत्कर्ष की सीमाओं का ग्रामीण, रेगिस्तानी, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में विस्तार करना;
- (vii) नवाचार और सृजनशीलता को बढ़ावा देने की दृष्टि से उच्च राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकी के केन्द्र स्थापित करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.—विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :-

- (i) अनुसंधान और ज्ञान की समन्वुति और प्रसार के लिए उपबन्ध करना और सामान्यतया तकनीकी शिक्षा और अध्ययन और संस्कृति की विभिन्न शाखाओं और उनके अन्तर शाखा क्षेत्रों का संवर्धन और प्रोन्नयन करना;
- (ii) विश्वविद्यालय निवेश में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण केन्द्र जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ. भा. त. शि. प. द्वारा स्थापित इसी प्रकार के विद्या केन्द्रों की स्थापना का उपबन्ध करना जिनका उपयोग किसी

- विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या उद्योगों के किसी समूह या किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा किये जा सके;
- (iii) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाओं या परीक्षणों का संचालन करना और उनके संबंध में शर्तें अधिकथित करना;
- (iv) परीक्षाओं या अन्य परीक्षणों के आधार पर या अन्यथा उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमे, उच्च माध्यमिकोत्तर डिप्लोमे, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- (v) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमे और उच्च माध्यमिकोत्तर डिप्लोमे और प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना, जिन्होंने,—
- (क) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है; या
- (ख) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अनुसंधान किया है;
- (vi) परिणियमों में विहितानुसार सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना;
- (vii) पाठ्यक्रमों या महाविद्यालयों की सम्बद्धता की और प्रबन्ध की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर संस्थाओं की मान्यता की शर्तें अधिकथित करना और संस्थाओं, संकायों और विषयों के शिक्षा सम्बन्धी संपादन के सन्नियम जो समय-समय पर

अधिकथित किये जायें और स्वयं का कालिक निर्धारण द्वारा या अन्यथा यह समाधान करना कि उन शर्तों को पूरा किया जाता है;

- (viii) किसी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ. भा. त. शि. प. द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों, यदि कोई हों, के अनुसार स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या, यथास्थिति, संस्था के रूप में पदाभिहित करना;
- (ix) सम्बद्धता और कालिक प्रत्यायन के लिए सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के शैक्षणिक सम्पादन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना ;
- (x) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं का तत्प्रयोजन के लिए स्थापित नसमुचित तंत्र के माध्यम से निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण का स्तर मुचित स्तर बनाये रखा जाता है और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कार्यशाला और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं ;
- (xi) मान्यताओं और विन्यासों को धारित और प्रबंधित करना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्ति पदक और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदान करना;
- (xii) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था, प्राधिकारी या संगठन से सहकार या सहयोग करना और ऐसे

- प्रयोजनों के लिए कतिपय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, प्राधिकारियों या संगठनों से ऐसे समुचित ठहराव करना जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों;
- (xiii) महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता का विखण्डन करना;
- (xiv) अनुसंधान और विकास, परामर्शी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे खोजी या नवाचारी क्रियाकलापों द्वारा और उद्योग, व्यापार या किसी अन्य गैर-सरकारी संगठनों के विभिन्न मुवक्किलों को सेवाएं देकर विश्वविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि की संभावनाओं की खोज करना;
- (xv) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन से विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोगी कार्यक्रमों को हाथ में लेना;
- (xvi) सहयोगी कार्यक्रमों के लिए विदेशी एजेन्सियों से, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम, नियम और विनियम के अध्यक्षीन रहते हुए निधियां प्राप्त करना;
- (xvii) विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए आचार संहिता, कार्यभार, संपादन मूल्यांकन के सन्नियमों को सम्मिलित करते हुए सेवा की शर्तें और ऐसे अन्य अनुदेश या निदेश अधिकथित करना जो विश्वविद्यालय की राय में शैक्षणिक स्तर के हित में आवश्यक हों;
- (xviii) तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आधारित परियोजनाओं के विकास कार्यक्रम और संसाधन जुटाने की दृष्टि से फीस प्रभारित करके बाहरी एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेना;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(11)

- (xix) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना जो परिनियमों द्वारा समय-समय पर विनियमित किये जायें;
- (xx) विभिन्न विभाग स्थापित, संधारित और प्रबन्धित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों;
- (xxi) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जो उसके समस्त या किन्हीं भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हों;
- (xxii) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रतिनिदेश से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों की अनुपालना करना और उनको कार्यान्वित करना।

6. अधिकारिता.—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और समस्त तकनीकी संस्थाएं, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के अनुसार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगी।

(2) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा,—

- (क) विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या
- (ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय

7(12) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निगम को सौंप दिया जाना या विशेषाधिकारों को देखा जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होगा.—विश्वविद्यालय जाति, वर्ग, पंथ या लिंग पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा :

परन्तु विश्वविद्यालय—

- (i) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को निर्बन्धित कर सकेगा;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, छात्राओं और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा।

8. निरीक्षण और जांच.—(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जो वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों,

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(13)
प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और उपस्कर को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं या किये जाने वाले अध्यापन और अन्य सभी संकर्मों का भी निरीक्षण करवाने या विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त संबंधी किसी भी मामले के संबंध में ऐसी ही रीति से जांच करवाने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करवाने का विनिश्चय करती है वहां वह इस बारे में कुल-सचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को सूचित करेगी, और कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुने जाने का अधिकार होगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल न्यायालय की वे सभी शक्तियां होंगी जो शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों और सारवान् वस्तुओं को पेश करने के लिए विवश करने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को होती हैं और उसे या उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष की कार्यवाहियां भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जायेंगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश से कुलपति को संबोधित करेगी और कुलपति ऐसी सलाह सहित, जो राज्य सरकार उस पर कार्रवाई किये जाने के लिए प्रस्तावित करे, राज्य सरकार के विचारों से बोर्ड को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तत्पश्चात् ऐसे समय के भीतर-भीतर, जो राज्य सरकार द्वारा नियत किया जाये, बोर्ड द्वारा की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करते हैं तो राज्य सरकार ऐसे किसी भी स्पष्टीकरण पर, जो विश्वविद्यालय के प्राधिकारी दें, विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगे।

(7) राज्य सरकार उप-धारा (1) के अधीन करवाये गये किसी निरीक्षण या जांच की प्रत्येक रिपोर्ट की और उप-धारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उप-धारा (6) के अधीन जारी प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेशों के अनुपालन या अननुपालन के संबंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की भी एक-एक प्रति कुलाधिपति को भेजेगी।

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी.—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) प्रतिकुलपति;
- (iv) वित्त अधिकारी;
- (v) कुल-सचिव;
- (vi) परीक्षा नियंत्रक;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (viii) सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (ix) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(15)

10. कुलाधिपति.—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर उसके दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कोई भी सम्मानित उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधधीन होगा।

(3) कुलपति का, यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाएं या अभिलेख प्रस्तुत करे जिनकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा प्रदत्त की जायें।

11. कुलपति —(1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार की सलाह से नियुक्त किया जायेगा —

- (i) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध या घटक महाविद्यालय से संबंधित कोई व्यक्ति न हो;
- (ii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा;
- (iii) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति।

(2) कुलपति ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए या तब तक जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा :

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलपति ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा

7(16) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)
संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का
हकदार होगा जो परिनिंयमों द्वारा विहित की जायें।

(4) जब कुलपति के पद की उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने
या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण कोई स्थायी रिक्ति हो जाये
तो वह कुलाधिपति द्वारा उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब
तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा उप-धारा (5)
के अधीन और अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जायेगी।

(5) जब कुलपति के पद की उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या
अन्यथा कोई अस्थायी रिक्ति हो जाये, या जब कोई अस्थायी व्यवस्था
उप-धारा (4) के अधीन आवश्यक हो जाये तब कुल-सचिव मामले की
रिपोर्ट तुरन्त कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य-संस्कार की सलाह से,
कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा (1) से उप-धारा (5) के अंतर्गत किसी बात के
होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कुलाधिपति द्वारा, राज्य
सरकार की सलाह से, तीन वर्ष से अनधिकार की कालावधि के लिए ऐसे
निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो राज्य-संस्कार अवधारित
करे।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग किसी भी समय अपना त्यागपत्र
ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से
कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति
द्वारा अवधारित की जायेगी और कुलपति को दी जाये।

(9) यदि कुलाधिपति की शर्तों के अनुसार कुलपति इस अधिनियम के
उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करता है या करने से
इनकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या
यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर
बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी

जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकेगा।

(10) उप-धारा (9) में निर्दिष्ट किसी जांच के लंबित रहने तक या उसे आसन्न मानकर कुलाधिपति आदेश कर सकेगा कि अगले आदेशों तक -

- (i) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा किन्तु वह ऐसी परिलब्धियां प्राप्त करता रहेगा जिनका वह उप-धारा (3) के अधीन अन्यथा हकदार होता;
- (ii) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति, इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे

7(18) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)
और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी,
प्राधिकारी या अन्य निकाय-को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम
में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी
कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए
अलाभकारी प्रभाव पड़ता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे
की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड
को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के
अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और
पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट
समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों
का प्रयोग करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

13. प्रतिकुलपति.—(1) कुलपति, यदि वह आवश्यक, समझे तो,
विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को प्रतिकुलपति नियुक्त कर
सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप
में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसादानुसार पद धारित करेगा।

(4) प्रतिकुलपति एक हजार रुपये प्रति मास का मानदंड प्राप्त
करेगा।

(5) प्रतिकुलपति, कुलपति का ऐसे मामलों में सहयोग करेगा जं
कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें औः
कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेग
और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जं
कुलपति द्वारा समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें।

14. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा। वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जायें।

(5) कुल-सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें या कुलपति द्वारा समय-समय पर जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

15. वित्त अधिकारी.- (1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा। वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) वित्त अधिकारी -

- (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ii) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों और विनिधानों का प्रबंध करेगा;
- (iii) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा;
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;
- (v) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबंधनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और
- (vi) धारा 35 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16. परीक्षा नियंत्रक.—(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(21)

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आर्डिनेन्सों में इस निमित्त किये गये उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिए आबद्ध होगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनके बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, किन्तु वह इस उप-धारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों पर भी उसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में उसे कुल-सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य समस्त इंतजाम करेगा और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश पर ही अन्यथा नहीं, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो पद के समस्त कर्तव्य परीक्षा नियंत्रक के पुनः पद ग्रहण करने या, यथास्थिति, रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

7(22) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.—(1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) सम्पदा अधिकारी, और
- (ii) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;
- (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;
- (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;
- (घ) छात्रों के पाठ्येत्तर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.—(1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(23)

19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.—धारा 9 के खण्ड (ix) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.—विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित किया जाये उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रबंध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) वित्त समिति;
- (iv) परीक्षा समिति;
- (v) संकाय;
- (vi) अध्ययन बोर्ड,
- (vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.—(1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (क) अध्यक्ष :-
विश्वविद्यालय का कुलपति।

(ख) पदेन सदस्य :-

- (i) शासन सचिव, वित्त विभाग;
- (ii) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;
- (iii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार;
- (iv) विश्वविद्यालय का कुल सचिव, सचिव।

स्पष्टीकरण.—(i) से (ii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिनी भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(ग) नामनिर्देशित सदस्य :-

- (i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
- (ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
- (iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- (v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले राज्य विधान-मंडल के दो सदस्य, और
- (vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्।

(घ) निर्वाचित सदस्य :-

विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों यदि कोई हों; के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, घटक महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं, उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर तकनीकी शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

(2) बोर्ड के एक-तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

23. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.—इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन रहते हुए, बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित और मंजूर करना;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियां अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;

7(26)

राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (व)

- (ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम स्थावर सम्पत्ति का अंतरण स्वीकार करना;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों व प्रशासन करना;
- (ङ.) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्-स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उसके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- (झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- (ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाना; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों का इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमन और अवधारण करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(27)

24. विद्या परिषद्.—(1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) कुलपति—पदेन अध्यक्ष;
- (ii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (iii) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
- (iv) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक;
- (v) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;
- (vi) निदेशक, तकनीकी शिक्षा;
- (vii) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (viii) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- (ix) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (x) घटक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
- (xi) संबद्ध महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर

कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(xii) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(3) विद्या परिषद के एक-तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

25. वित्त समिति.—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(i) कुलपति-अध्यक्ष;

(ii) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;

(iii) शासन सचिव, वित्त विभाग;

(iv) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(v) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव;

(vi) परीक्षा नियंत्रक;

(vii) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे अधिकारी को नामनिर्देशित कर सकेगा जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर बोर्ड को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी और किन्हीं भी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रकार नियत सीमाओं का पुनरीक्षण कर सकेगी और नियत सीमाएं बोर्ड पर बाध्यकारी होंगी।

(4) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

26. संकायों की संरचना और कृत्य.—(1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- (i) संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष;
- (ii) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;
- (iii) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (iv) संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष;
- (v) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. परीक्षा समिति.—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों में उपबंधित किया जाये।

(2) समिति, अनुसीमन और सारणीकरण को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का साधारणतया पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्य करेगी, अर्थात् :-

- (i) परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और, यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
- (ii) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उस पर विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- (iii) परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;

7(30) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

(iv) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति इतनी उप-समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझें, और विशिष्टतया किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने और उनका विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, परीक्षा समिति के लिए या, यथास्थिति, उप-समिति या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उप-धारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

28. विश्वविद्यालय का अध्यापन.—(1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों या संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

29. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.—(1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे

प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी

7(32) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)
विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

30. विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.—विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

31. सेवानिवृत्ति की आयु.—परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु-प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

32. पेंशन या भविष्य निधि.—(1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों में विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

33. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.—(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(33)
संविदा संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। संविदा, सेवा की शर्तों के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

34. विश्वविद्यालय निधि.—(1) विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय निधि' के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबन्ध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात् :-

- (i) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान;
- (ii) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- (iii) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों;
- (iv) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें विश्वविद्यालय निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्ययों की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि में से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

35. राज्य सरकार का नियंत्रण.—जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ,

7(34) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)
निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो
सकेगी, अर्थात् :-

- (i) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ii) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (iii) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी ;
- (iv) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (v) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरण;
- (vi) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना;
- (vii) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.—पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

36. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.—यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता अमुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

37. परिनियम.—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा :-

- (i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हों;
- (iii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (iv) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;
- (v) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- (vi) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (vii) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;

- (viii) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति;
- (ix) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- (x) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;
- (xi) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं; और
- (xii) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा या जो आर्डिनेन्सों या विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे।

38. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.—(1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित या निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्ररेणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(37)

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसके लिए अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

39. आर्डिनेन्स.—इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (i) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ii) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या निवास के अन्य स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

7(38) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण;

(v) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य मामला जिस पर विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन कार्यवाही की जानी है।

40. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.—(1) बोर्ड इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बंध को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर आक्षेप के दारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, प्रबन्ध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात् या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

41. विनियम.—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा :-

(i) अपनी बैठकों में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(39)

(ii) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और

(iii) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित ; और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्स द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीख का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसे रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

42. छात्रों का निवास स्थान.—छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास-सुविधा में, आर्डिनेन्सों के द्वारा विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निवास करेंगे।

43. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, प्रयोग में लाये जाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

44. वार्षिक रिपोर्ट.—विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व परिचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

7(40) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

45. लेखे और संपरीक्षा.—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(3) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

46. अस्थायी व्यवस्था.—(1) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, कर सकेगा।

47. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.—जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जो राज्य सरकार निदिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

48. अवशिष्ट उपबंध.—बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा।

49. कठिनाइयों का निराकरण.—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा —

- (i) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या
- (ii) ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
- (iii) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से बारह नास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता

7(42) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)
है कि ऐसे कोई आदेश नहीं किये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में की आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

50. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2006 का अध्यादेश सं. 1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

गुमान सिंह,

शासन सचिव।

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(43)

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 9, 2006

No. 2 (9) Vidhi/2/2006.- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Takaneckee Vishvavidhyalaya Adhinyam, 2006 (2006 Ka Adhinyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2006

(Act No 8 of 2006)

(Received the assent of the Governor on the 9th day of
April, 2006)

An
Act

*to establish and incorporate the Rajasthan Technical University in
the State of Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the
Fifty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. – (1) This Act
may be called the Rajasthan Technical University Act, 2006.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall be deemed to have come into force on and from
31st December, 2005.

2. Definitions. – In this Act, unless the subject or context otherwise requires, –

- (i) "Academic Council" means the Academic Council of the University as constituted under section 24;
- (ii) "affiliated college" means a college or institution which has been granted affiliation by the University;
- (iii) "AICTE" means All India Council for Technical Education, established under All India Council for Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987);
- (iv) "authorities" means the authorities of the University as specified by or under this Act;
- (v) "Board" means the Board of Management of the University as constituted under section 22;
- (vi) "bodies" means the bodies of the University formed by the respective authorities;
- (vii) "collaboration" means collaborative academic activity of the University with other universities, academic institutions (local, regional, national or international), research institutions and organizations (research, agriculture, industry, trade and commerce);
- (viii) "constituent college" means a college or an institution which imparts technical education and is run and maintained by the University and includes a Faculty of the University;
- (ix) "Dean" means head of a Faculty of the University;
- (x) "Department" means a Department established, maintained and managed by the University;
- (xi) "Director" means a head of an institution including a centre, or a school of the

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(45)

University as designated by the Board of Management;

- (xii) "Faculty" means a Faculty of the University;
- (xiii) "Government aided technical institution" means technical institution receiving grant-in-aid from the State Government;
- (xiv) "institutions" means Government aided technical institutions and private unaided technical institutions;
- (xv) "management" means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of any trust registered under the Rajasthan Public Trusts Act, 1959 (Act No. 42 of 1959) or any society registered under the Rajasthan Societies Registration Act, 1958 (Act No. 28 of 1958) under the management of which one or more colleges or recognized institutions or other institutions are conducted and admitted to the privileges of the University;
- (xvi) "Ordinances" means Ordinances of the University made under this Act;
- (xvii) "Principal" means the Chief Executive Officer of a college, a Government aided technical institution or a private unaided technical institution;
- (xviii) "private un-aided technical institution" means an institution set up by a private management with the prior approval of AICTE to conduct degree or diploma level courses of technical education and not receiving grant-in-aid from the State Government;
- (xix) "Regulations" means Regulations of the University made under this Act;
- (xx) "Statutes" means Statutes of the University made under this Act;

- (xxi) "teacher" means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (xxii) "technical education" means programmes of education, research and training in Engineering, Technology, Architecture, Management, Town Planning, Pharmacy, Computer applications and Applied Arts & Crafts and such other programmes as the AICTE may, by notification in the Official Gazette, declare;
- (xxiii) "technical institutions" means institutions conducting programmes in the field of technical education;
- (xxiv) "University" means the Rajasthan Technical University established under this Act;
- (xxv) "University Department" means a Department established and maintained by the University;
- (xxvi) "University teacher" means a teacher appointed by the University.

CHAPTER II THE UNIVERSITY

3. Incorporation of the University.—(1) The Chancellor and the first Vice-chancellor of the University and the first members of the Board and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, will constitute a body corporate by the name of "Rajasthan Technical University" and shall have perpetual succession and a common seal and may by that name sue and be sued.

(2) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which

may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the prior approval of the State Government.

(3) The Headquarters of the University shall be at Kota, which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

4. The objects of the University: - Following shall be the objects of the University, namely:-

- (i) to disseminate, create and preserve the knowledge in the field of technical education for the advancement of mankind and understanding by the teaching, training, research, in general, and in particular :-
 - (a) to promote total quality and cost effective management of engineering, technology, management and other technical institutions;
 - (b) to provide a network of technical education in the State to meet the demand of quality technical education and research;
 - (c) to create a system of management for technical education based on the scientific tools of decision making and information systems;
- (ii) to develop work culture and promote dignity of labour through applied components in the syllabi and to promote entrepreneurship among students so as to make technical education a valid means of job creation, rather than creating the job seekers;

7(48) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

- (iii) to promote better interaction and co-ordination among different universities and colleges by all such means, generally to improve the governance of the University, and facilities it provides for technical education;
- (iv) to generate and promote a sense of self-respect and dignity amongst the weaker sections of the society;
- (v) to strive to promote competitive merit and excellence as the sole guiding criterion in all academic and other matters relating to students;
- (vi) to extend its frontiers of academic excellence to rural, desert, tribal and backward areas;
- (vii) to set up centres of advanced technology in areas of high national relevance, with a view to fostering innovation and creativity.

5. Powers and duties of the University.- The University shall have the following powers and duties, namely :-

- (i) to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge, and generally to cultivate and promote the technical education and other branches of learning and culture and their interdisciplinary areas;
- (ii) to provide for establishment, on the University campus, of autonomous institutions like inter-university centres, research laboratories, modern instrumentation centres and like centres of learning, set up by the Central Government or State Government and University Grants Commission or AICTE, which may be used by a

- university or college or group of universities or colleges or industries or any Non-Government Organization;
- (iii) to admit students to the various courses of study of the University and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof;
- (iv) to institute and award degrees, post-graduate diplomas, post-senior secondary diplomas, certificates and other academic distinctions on the basis of examinations or by other tests or otherwise;
- (v) to hold examinations and confer degrees and post-graduate diplomas and award post-senior secondary diplomas and certificates and other academic distinctions to, and on, persons, who -
- (a) have pursued a course of study in the University, constituent or affiliated college or institutions; or
- (b) have carried on research in the University, constituent or affiliated colleges or institutions;
- (vi) to confer honorary degrees or other academic distinctions as prescribed by the Statutes;
- (vii) to lay down the conditions of affiliation of courses or colleges and recognition of institutions taking into account the credibility of the Management and the norms of academic performance of institutions, faculties and subjects, as may be laid down, from time to time, and satisfy itself by periodical assessment or otherwise that those conditions are fulfilled;

- (viii) to designate a University Department, constituent college, affiliated college or institution, as an autonomous University Department, constituent college, affiliated college or institution, as the case may be, in accordance with the guidelines, if any, laid down by the University Grants Commission or AICTE;
- (ix) to monitor and evaluate the academic performance of affiliated colleges and recognized institutions for affiliation and periodical accreditation;
- (x) to inspect, where necessary, affiliated colleges and recognized institutions through suitable machinery established for the purpose, and take measures to ensure that proper standards of instruction, teaching and training are maintained by them, and adequate library, laboratory, hospital, workshop and other academic facilities are provided for;
- (xi) to hold and to manage trusts and endowments and institute and award fellowships, travelling fellowships, scholarships, studentship medals and prizes for teachers and students of the University and colleges;
- (xii) to co-operate or collaborate with any other University, institution, authority or organization for research and advisory services and for such purposes to enter into appropriate arrangement with other universities, institutions, authorities, or organizations to conduct certain courses as the situation may demand;
- (xiii) to rescind affiliation granted to colleges;

Registrar

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(51)

- (xiv) to explore the possibilities of augmenting the resources of the University by exploring or innovating activities such as research and development, consultancy, training programmes and providing services for different clients from industry, trade or any other Non-Government Organizations;
- (xv) subject to any other law for the time being in force, to undertake academic collaboration programmes with universities and institutions abroad, with the approval of the State Government;
- (xvi) to receive funds for collaboration programmes from foreign agencies subject to any Act, rules and regulations of the Central Government and State Government in that behalf;
- (xvii) to lay down for University teachers, service conditions including code of conduct, workload, norms of performance appraisal, and such other instructions or directions as, in the opinion of the University, may be necessary in the interest of academic standard;
- (xviii) to undertake development programmes in technical education, research, consultancy-based projects and training programmes for outside agencies, by charging fees, so as to generate resources;
- (xix) to fix, demand and receive or recover such fees and other charges as may be regulated by the Statutes, from time to time;
- (xx) to establish, maintain and manage various Departments as may be necessary to fulfil the objects of the University;

- (xxi) to do all such other acts and things as may be necessary for or incidental or conducive to the attainment of all or any of its objects;
- (xxii) to comply with and carry out any directives issued by the State Government from time to time, with reference to above powers, duties and responsibilities of the University.

6. Jurisdiction. - (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force the jurisdiction of the University shall extend to whole of the State of Rajasthan and all technical institutions shall be affiliated to the Rajasthan Technical University in accordance with the Statutes, Ordinances and Regulations made under this Act.

(2) The State Government may, by order in writing –

- (a) require any institute, institution or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government college situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college of the University. The land, buildings, laboratories, equipments, books and any other properties of such college shall then vest in the University and the

officers, teachers and employees of such college, after being found suitable through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or as the case may be employees of the University.

7. University to be open to all classes and creeds.- The University shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex:

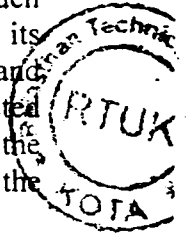
Provided that the University may -

- (i) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the University;
- (ii) make reservations in favour of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, girl students and other categories in accordance with any law or orders of the State Government for the time being in force.

8. Inspections and Inquiry. - (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations, teaching and all other works conducted or done by the University or, to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Vice-Chancellor may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908), for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling



production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), and the proceedings before him or them shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry, and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

(5) The Vice-Chancellor shall then, within such time as the State Government may fix, submit a report to the State Government of the action taken or proposed to be taken by the Board.

(6) If the University authorities do not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, the State Government may, after considering any explanation which the University authority may furnish, issue such directions as it may think fit, and the University authority shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5), and of every direction issued under sub-section (6), and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

CHAPTER III

Officers of the University

9. Officers of the University. - The following shall be the officers of the University, namely:-

- (i) the Chancellor;
- (ii) the Vice-Chancellor;
- (iii) the Pro-Vice-Chancellor;

- (iv) the Finance Officer;
- (v) the Registrar;
- (vi) the Controller of examination;
- (vii) the Deans of the Faculties;
- (viii) the Estate Officer and Dean of the Students Welfare;
- (ix) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

10. The Chancellor. - (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall when present, preside at the convocations thereof.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University, as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder.

11. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (i) one person nominated by the Board not being a person connected with the University, or any affiliated or constituent college;
- (ii) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee;
- (iii) two persons nominated by the State Government.

7(56) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty- two years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for re-appointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the Statutes.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(9) If, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(10) During the pendency, or in contemplation of any inquiry referred to in sub-section (9), the Chancellor may order that till further orders –

- (i) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (3);
- (ii) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

12. Powers and duties of the Vice-Chancellor. - (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration matters of concern to the University. He shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days of the date on which the action is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

13. The Pro-Vice-Chancellor. - (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get an honorarium of rupees one thousand per month.

(5) Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

14. Registrar. – (1) The Registrar shall be the whole time officer of the University.

(2) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers in the services of the State of Rajasthan.

(4) The Registrar shall be responsible for the custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* Secretary of the Board and Academic Council. He shall place before it all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall receive applications for entrance to the University and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other information as may be deemed necessary.

(5) The Registrar shall perform such other duties as may be prescribed by Statutes or Ordinances or required of him from time to time by the Vice-Chancellor.

15. Finance Officer. – (1) The Finance Officer shall be the whole time officer of the University.

(2) The Finance Officer shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(3) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Finance Officer shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service.

(4) The Finance Officer shall –

- (i) advise in regard to the financial policy of the University and be responsible for the preparation of its budget and for the presentation thereof to the Board through the Vice-Chancellor;

- (ii) manage the properties, movable and immovable, and investments of the University;
- (iii) keep all moneys belonging to the University in a Scheduled Bank or in the Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., or Central Co-operative Bank except the amounts needed as imprest cash (to be prescribed by the Vice-Chancellor) in transacting business of the University;
- (iv) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
- (v) disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statutes or for which provision is required to be made by the Statutes but has not been made; and
- (vi) ensure the compliance of the provisions of section 35.

16. The Controller of Examination. – (1) The Controller of Examination shall be a whole time officer of the University.

(2) The Controller of Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor in accordance with the provision of Ordinances made in this behalf with approval of the Board.

(3) The Controller of Examination shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or as may be required from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor but he shall not, by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examination shall have administrative control of Examination and over the employees working under him and have, in this regard, all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examinations Committee, the Controller of Examination shall conduct the examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examination shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examination is, for any reason, unable to act or the office of the Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

17. Estate Officer and Dean of Students Welfare. – (1)
The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (i) The Estate Officer, and
- (ii) The Dean of Students Welfare.

(2) The Estate Officer shall be incharge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Students Welfare shall have the following duties, namely:-

- (a) to make arrangements of the housing of students,
- (b) to direct a programme of students counselling,
- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor,
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students,
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University, and

- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

18. Deans of Faculties and their functions. – (1) There shall be a Dean of each Faculty.

(2) ~~The Deans of Faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner as may be prescribed by the Statutes.~~

(3) ~~The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.~~

19. Other officers and employees. – The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (ix) of section 9, and of the employees of the University shall be such as provided in this Act or as prescribed by Statutes, Ordinances and Regulations.

20. Remuneration of officers and employees. – No officer or employee of the University shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save as may be provided for in the Statutes.

CHAPTER IV

Authorities of the University

21. Authorities of the University. – The following shall be the authorities of the University; namely:-

- (i) The Board of Management;
- (ii) The Academic Council;
- (iii) The Finance Committee;
- (iv) The Examination Committee;
- (v) The Faculties;
- (vi) Boards of Studies;
- (vii) Such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

22. Constitution and composition of the Board of Management.— (1) The Board shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following as members, namely:-

(a) Chairman:-

The Vice-Chancellor of the University.

(b) Ex-officio Members:-

- (i) the Secretary to the Government, Finance Department;
- (ii) the Secretary to the Government, Technical Education Department;
- (iii) the Director of Technical Education, Government of Rajasthan;
- (iv) the Registrar of the University, Secretary.

Explanation :- *Ex-officio* members mentioned at (i) to (ii) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of Deputy Secretary to the Government of Rajasthan.

(c) Nominated Members:-

- (i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year;
- (ii) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor for one year;
- (iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
- (iv) two Principals of affiliated colleges, one from the Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government for one year;

- (v) two members of State Legislature to be nominated by the Speaker for three years; and
- (vi) two eminent educationists, to be nominated by the State Government for three years.

(d) Elected Members:-

Two teachers of the University or its constituent colleges, if any, who have put in not less than seven years teaching experience in any institution of higher technical education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Directors of the constituent colleges, to be elected by the teachers of the University and its constituent colleges from amongst themselves for three years.

(2) One third of members of the Board shall constitute the quorum for a meeting.

(3) The Chairman of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed by the Statutes.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed by the Statutes.

(5) The minutes of meetings of the Board shall be recorded and maintained by the Secretary of the Board.

23. Duties and functions of the Board. – Subject to other provisions of this Act, the duties and functions of the Board shall be as follows:–

- (a) to approve and sanction the budget of the University;

- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for the specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed by the Statutes;
- (g) to direct the form and use of the common seal of the University;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary, as it deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner specified in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as

may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

24. Academic Council. - (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

- (i) the Vice-Chancellor-*ex-officio* Chairman;
- (ii) Deans of Faculties;
- (iii) one Professor from each Faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (iv) one Principal/Director of a constituent college to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (v) Secretary to the Government, Technical Education Department;
- (vi) Director, Technical Education;
- (vii) Chairmen, Boards of Studies;
- (viii) two Principals of affiliated Colleges, one from Government Colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government;
- (ix) two persons having special attainment in the field of the studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
- (x) one teacher other than the Professors, from a constituent college or University Department having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (xi) one teacher other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government; and

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(67)

(xii) the Registrar of the University, Member-Secretary.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

(3) One third of the members of the Academic Council shall constitute the quorum for a meeting.

25. The Finance Committee. - (1) The Finance Committee shall consist of—

- (i) the Vice-Chancellor- Chairman;
- (ii) the Secretary to the Government, Technical Education Department;
- (iii) the Secretary to the Government, Finance Department;
- (iv) the Pro-Vice-Chancellor, if any;
- (v) the Registrar of the University;
- (vi) the Controller of Examinations;
- (vii) the Finance Officer, who shall also be the Secretary of the Committee.

(2) A member referred to clause (ii) or clause (iii) of subsection (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, nominate an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government, to act on his behalf.

(3) The Finance Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resource of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits fixed shall be binding on the Board.

(4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

26. Composition and functions of Faculties. – (1) There shall be such Faculties in the University as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each Faculty shall consist of the following:-

- (i) Dean of the Faculty – Chairman;
- (ii) University Professors of the subjects assigned to the Faculty;
- (iii) Chairmen of the Boards of Studies in the Faculty;
- (iv) one post-graduate College Principal and one Post-graduate Department Head in each subject of the Faculty from affiliated colleges, nominated by the State Government;
- (v) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) Faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

27. Examination Committee. – (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely:-

- (i) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;
- (ii) to review from time to time the result of the University examinations and submission of report thereon to the Academic Council;
- (iii) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;

- (iv) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examinations Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3) to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

28. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University Departments or in colleges or institutions.

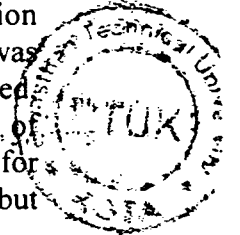
(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed by the Ordinances.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

29. Supplementary provisions relating to membership.-

(1) All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any Authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment, nomination or election according as the member whose place became vacant was appointed, nominated or elected and the person appointed, nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long as he holds the other office and thereafter till his successor is duly nominated, appointed or elected.



(3) The Board may remove any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or any employee of the University on the ground that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming the prestige of the University:

Provided that no such person or employee shall be removed under this sub-section unless he has been afforded a reasonable opportunity by the Board, to show cause as to why he should not be so removed and such cause has been considered:

Provided further that prior approval of the State Government will be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed, nominated or elected, as or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his decision, and the decision of the Chancellor thereon shall be final.

30. Proceedings of University authorities and bodies not to be invalidated by reason of any vacancy. – No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalidated by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

31. Age of retirement. – Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

32. Pension or Provident Fund. - (1) For the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, the University shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed in the Statutes, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) Provision shall be made in Statutes to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

33. Teachers and Officers of the University.- (1) Save as otherwise provided in this Act, the appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

34. University Fund. – (1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University Fund.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into the University Fund, namely:-

- (i) any contribution or grant by the State Government;
- (ii) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (iii) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (iv) such other moneys as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matters to which the University Fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

(4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University Fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

35. Control of the State Government .- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (i) creating of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (ii) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (iii) grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (iv) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (v) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (vi) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received;
- (vii) taking of any decision regarding affiliated colleges resulting in increase of financial liability, direct or indirect, on the State Government.

Explanation. - The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may in long term likely to cause financial implications to the State Government.

36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure. - If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial

mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure. it may, by a notification, declare that the finance of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

37. Statutes. — Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall in particular provide for the following:

- (i) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (ii) the appointment, nomination or election and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (iii) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University;
- (iv) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
- (v) the constitution of pension, gratuity, insurance and provident funds for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (vi) the conferment of honorary degrees;
- (vii) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of Departments;
- (viii) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (ix) the moneys to form part of and to be paid into the University Fund and the matters to which the Fund may be applied and appropriated;

7(74) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 भाग 4 (क)

- (x) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;
- (xi) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and
- (xii) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed otherwise than by the Ordinances or the Regulations.

38. Statutes how made. – (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter provided.

(2) The Board may take into consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statutes passed by the Board shall be valid or shall come into force until they are assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either *suo motu* or on the advice of the State Government, may, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

39. Ordinances. – Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) the courses of study, admission or enrolment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (ii) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (iii) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefore and other related matters;
- (iv) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University;
- (v) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

40. Ordinances how made. - (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matters shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he shall, as soon as possible, inform the Board of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the

order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

41. Regulations. - (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances -

- (i) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (ii) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulations; and
- (iii) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct amendment in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

42. Residence of Students. - The students shall reside in accommodation provided by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions prescribed by the Ordinances.

43. Delegation of Powers. - The Board may by Statutes delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed in the Statutes.

44. Annual Report. - The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report, as approved by the Board, shall be sent to the Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

45. Accounts and audit. - (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accrued to or received by the University from whatever source and, all amounts disbursed, or paid shall be entered in the accounts.

(2) Such accounts shall be audited in such manner and by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University Fund.

(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

46. Temporary arrangements. (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor to carry on the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments, subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointments.

47. Reference to government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding officers. Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then, if that designation is altered or that office ceases to exist the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government may direct.

48. Residuary provisions. - The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt with in this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final.

49. Removal of difficulties. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulties, in the areas and

7(78) राजस्थान राज-पत्र, अप्रेल 10, 2006 भाग 4 (क)
in the matters covered by this Act, by order published in the
Official Gazette, –

- (i) direct that this Act shall during such period, as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act as it may deem fit to be necessary or expedient, or
- (ii) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act.
- (iii) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any such order should not be made, such order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter may be referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall, after taking such advice from the State

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, अप्रैल 10, 2006 7(79)

Government as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

50. Repeal and savings. - (1) The Rajasthan Technical University Ordinance, 2005 (Ordinance No. 1 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

गुमान सिंह,
Secretary to the Government.

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन)

विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) की धारा 2 के खण्ड (xxii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नगर योजना" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "कम्प्यूटर उपयोजन" के पूर्व आयी हुई विद्यमान अभिव्यक्ति "फार्मसी," हटायी जायेगी।

THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2013

*A
Bill*

further to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Technical University (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 10th June, 2013.

2. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 8 of 2006.- For the existing section 8 of the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons, as he or she may direct—

(a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipments; or

(b) of any institution or hostel maintained by the University; or

(c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or

(d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.”.

3. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 8 of 2006.- For the existing section 11 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“11. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed by the statutes.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(7) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(8) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(9) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(10) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(11) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.

4. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 8 of 2006.- For the existing section 36 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“36. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.”.

5. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 8 of 2006.- For the existing section 45 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :-

“45. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Finance Officer shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget of the University for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the annual financial estimates prepared by the Finance Officer shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Finance Officer who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”.

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Technical University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 14 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the University and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which University can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it had been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, assumption of financial control by the State Government as emergency measure and accounts and audit in the Rajasthan Technical University Act, 2006.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Technical University Ordinance, 2013 (Ordinance No. 14 of 2013) on 10th June, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 12th June, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

Minister Incharge.

**REASONS FOR PROMULGATION OF THE RAJASTHAN TECHNICAL
UNIVERSITY (AMENDMENT) ORDINANCE, 2013 (ORDINANCE NO.14 OF
2013)**

There has been good harmony between the University and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which University can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it has been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. visitation powers of Chancellor, retirement age of Vice-Chancellor, assumption of financial control by the State Government as emergency measure and accounts and audit in the Rajasthan Technical University Act, 2006.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Rajasthan Technical University Ordinance, 2013 (Ordinance No. 14 of 2013) on 10th June, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV(B), Extraordinary, dated 12th June, 2013.

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clauses 3 and 5 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 11 (3) and the date before which budget for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 45 (2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

Minister Incharge.